

प्रेषक,

आर०सी० अग्रवाल,  
अपर सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,  
नगर पंचायत,  
बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री,  
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 17: जनवरी, 2011

**विषय:-** तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों की प्रत्याशा में गैर निर्वाचित नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2011-12 की चतुर्थ किश्त (चतुर्थ त्रैमास) से माह-जनवरी, 2012 हेतु धनराशि का तदर्थ आधार पर संकमण।

महोदय,

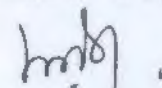
उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों की प्रत्याशा में शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार गैर नगर पंचायतों को चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 की चतुर्थ किश्त (चतुर्थ त्रैमास) से माह-जनवरी, 2012 हेतु तदर्थ आधार पर रू० 416000.00 (₹ चार लाख सोलह हजार मात्र) की धनराशि आवंटित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(धनराशि हजार रू० में)

क्र० सं०	नगर पंचायत का नाम	चतुर्थ किश्त हेतु कुल देय धनराशि	चतुर्थ किश्त से माह-जनवरी हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4
1-	बद्रीनाथ	625	208
2-	केदारनाथ	375	125
3-	गंगोत्री	250	83
	योग:-	1250	416

2- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संकमित की जा रही है:-

- (1) संकमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। संकमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या-1674/XXVII(1)/2006, दिनांक 22 नवम्बर, 2006 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।
- (2) नगर विकास विभाग संकमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे। कोषागार से आहरित धनराशि का बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।
- (3) निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, निकायों को आवंटित धनराशि के समय से उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।



- (4) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- इस सम्बंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेत्तर-01-नगरीय स्थानीय निकाय-193-नगर पंचायतें/नोटिफाइड एरिया/कमेटी आदि-00-04-राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(आर०सी० अग्रवाल )  
अपर सचिव।

संख्या:- 42 / (1) / XXVII(1)/2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
- 3- जिलाधिकारी-उत्तरकाशी/चमोली/रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड।
- 4- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- निदेशक, शहरी एवं नगरीय विकास, 43/6, माता मन्दिर मार्ग, धर्मपुर, देहरादून।
- 6- निदेशक, कोषागार एवं लेखा हकदारी, 23-लक्ष्मी रोड़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- वरिष्ठ जिला कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग।
- 8- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- 9- एन० आई०सी० सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 10- वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(आर.सी.अग्रवाल)  
अपर सचिव।